

# न्यूज टुडे

## अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अनुसार इजरायली हमले में ईरान की भूमिगत नतांज यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी प्रभावित हुई

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईरान की यूरेनियम संवर्धन (Uranium enrichment) सुविधाओं को हुए नुकसान को लेकर IAEA के खुलासे से परमाणु ठिकानों और सामग्रियों की सिक्योरिटी एवं सेफ्टी को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

न्यूक्लियर सिक्योरिटी के बारे में

परिभाषा:

- न्यूक्लियर सिक्योरिटी का अर्थ निम्नलिखित का पता लगाना, रोकना और प्रतिक्रिया करना है-
  - परमाणु सुविधाओं व सामग्रियों तक अनधिकृत पहुंच व उन्हें हटाने का प्रयास करना;
  - उन्हें भौतिक क्षति पहुंचाना और अवैध तरीके से परमाणु सामग्री का हस्तांतरण करना; या
  - परमाणु या रेडियोलॉजिकल सामग्री या उनसे जुड़ी सुविधाओं से संबंधित अन्य दुर्भावनापूर्ण कृत्य।
- वहीं न्यूक्लियर सेफ्टी से आशय परमाणु सामग्री या परमाणु ठिकानों की दुर्घटनाओं से सुरक्षा करना तथा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकना है, ताकि इससे होने वाले विकिरण के खतरों को टाला जा सके।
- न्यूक्लियर सेफ्टी बनाम सिक्योरिटी: न्यूक्लियर सिक्योरिटी के तहत दुर्भावनापूर्ण खतरों (जैसे आतंकवाद, सुविधाओं को नुकसान पहुंचाना आदि) से निपटने के प्रयास किए जाते हैं। वहीं न्यूक्लियर सेफ्टी दुर्घटनाओं एवं त्रुटियों की रोकथाम से संबंधित है।

न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में IAEA की भूमिका

- स्थापना: IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्वायत्त संगठन है।
  - भारत इस संस्था का संस्थापक सदस्य है।
- कार्य: यह संस्था परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तथा फूड सेफ्टी, कैंसर उपचार और सतत विकास में परमाणु तकनीकों का उपयोग जैसे विषयों पर कार्य करती है।
- न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी पर कन्वेंशंस:
  - परमाणु सामग्री के भौतिक संरक्षण पर कन्वेंशन: यह परमाणु सामग्री के भौतिक संरक्षण पर पहला बहुपक्षीय समझौता और कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
  - रेडियोएक्टिव स्रोत की सिक्योरिटी और सेफ्टी पर आधार संहिता: यह IAEA द्वारा जारी वैधानिक रूप से गैर-बाध्यकारी दिशा-निर्देश है।
  - न्यूक्लियर सेफ्टी पर कन्वेंशन (CNS): इसका उद्देश्य भूमि पर असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करने वाले अनुबंधित पक्षकारों को उच्च स्तर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध करना है।
  - न्यूक्लियर सेफ्टी पर वियना घोषणा-पत्र: इसका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं की रोकथाम करना और रेडिएशन के प्रभावों को कम करना है।

न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए संयुक्त राष्ट्र की अन्य पहलें

- आतंकवादी बमबारी के दमन पर कन्वेंशन (Convention for the Suppression of Terrorist Bombings): इसमें रेडियोएक्टिव सामग्री के उपयोग वाले विस्फोटक हमलों सहित किन्हीं अन्य विस्फोटक हमलों की रोकथाम के लिए भी उपाय किए गए हैं।
- परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism: ICSANT): यह कन्वेंशन सदस्य देशों पर परमाणु आतंकवाद को अपराध घोषित करने का दायित्व डालता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प:
  - आतंकवाद-रोधी व्यापक उपाय;
  - गैर-राज्य अभिकर्ताओं को सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) हासिल करने से रोकना आदि।

## केंद्रीय वित्त मंत्री ने फिनटेक फर्मों से कृषि क्षेत्रक और ग्रामीण क्षेत्रों में नए बाजार विकसित करने का आह्वान किया

वित्त मंत्री ने बल देकर कहा कि फिनटेक कंपनियों को ग्रामीण भारत को केवल सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि नए बाजार बनाने के एक अच्छे अवसर के रूप में भी देखना चाहिए।

फिनटेक सेक्टर के बारे में

- फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां वे कंपनियां होती हैं, जो तकनीक के जरिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं।
- फिनटेक सेक्टर में डिजिटल पेमेंट, वैकल्पिक ऋण (जैसे क्राउडफंडिंग), इंश्योरेंस (बीमा से जुड़ी तकनीक), वेल्थ टेक (निवेश प्लेटफॉर्म) और इनेबलिंग टेक (जैसे AI एवं बिग डेटा के जरिए सेवाएं) शामिल हैं।
- भारत का फिनटेक इकोसिस्टम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है और यह 14% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रहा है।

ग्रामीण भारत में फिनटेक सेक्टर की भूमिका:

- वित्तीय समावेशन: मोबाइल ऐप और डिजिटल वॉलेट के जरिए UPI के माध्यम से उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचती हैं, जिनके पास बैंक खाता नहीं है।
  - उदाहरण के लिए: आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (AEPs)।
- ऋण तक आसान पहुंच: वैकल्पिक डेटा का उपयोग करके किसानों और लघु व्यवसायों को छोटे कर्ज (माइक्रो लोन) प्रदान करती हैं।
  - उदाहरण के लिए: क्राप फंड्स जैसे एग्री-फिनटेक प्लेटफॉर्म किसानों की लेन-देन हिस्ट्री, खेती के उत्पादन आदि के आधार पर उनकी ऋण लेने की योग्यता तय करते हैं।
- कृषि सहायता: ऐप किसानों को मंडियों के भाव, मौसम की जानकारी और बीमा जैसी सेवाएं देते हैं, जिससे वे सीधे खरीदारों से जुड़ सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए: कृषि मंत्रालय के एग्रीमार्केट मोबाइल ऐप और फसल बीमा मोबाइल ऐप।
- डिजिटल भुगतान और पैसे भेजना: कम खर्च, विप्रेषण (Remittance) और सुरक्षित लेन-देन से नकद पैसे का कम इस्तेमाल होता है।
  - उदाहरण के लिए: UPI से जुड़े ऐप्स जैसे- Paytm और PhonePe अब ग्रामीण इलाकों में लेन-देन के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।



ग्रामीण इलाकों में फिनटेक सेक्टर के समक्ष मौजूद चुनौतियां:

- डिजिटल विभाजन: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे- इंटरनेट कनेक्टिविटी) और डिजिटल साक्षरता दोनों के अभाव के कारण लोग (विशेष रूप से महिलाएं और हाशिए पर मौजूद लोग) फिनटेक ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते।
- डिजिटल सेवाओं पर विश्वास की कमी: लोग डिजिटल वित्तीय सेवाओं से अनजान होते हैं। इसके अलावा, साइबर ठगी जैसे नकारात्मक अनुभव और नकद पैसे की आदत की वजह से इन सेवाओं पर भरोसा नहीं करते।
- भौगोलिक और भौतिक बाधाएं: दूर-दराज के इलाकों में पारंपरिक बैंकिंग सुविधाओं की कमी के कारण फिनटेक कंपनियों के लिए हर ग्रामीण ग्राहक तक पहुंचना और सेवाएं देना मुश्किल हो जाता है।

## यू. एस. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी प्रदान की

FDA की मंजूरी से अब यह दवा WHO प्रीक्वालिफिकेशन के लिए पात्र हो गई है। इससे अलग-अलग देशों में इसे जल्दी स्वीकृति मिल सकती है।

WHO प्रीक्वालिफिकेशन ऑफ़ मेडिसिन्स प्रोग्राम (PQP) यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दवा खरीद एजेंसियां जो दवाएं सप्लाई करती हैं, वे गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के स्वीकार्य मानकों को पूरा करती हैं।

लेनाकैपाविर के बारे में

- लेनाकैपाविर एक एंटीरेट्रोवायरल दवा है। इसका उपयोग HIV की रोकथाम के लिए प्री-एक्सपोज़र प्रोफ़िलैक्सिस (PrEP) के रूप में किया जाता है।
- PrEP एक ऐसी दवा है, जो उन HIV नैगेटिव व्यक्तियों में HIV संक्रमण के जोखिम को कम कर सकती है, जिन्हें वायरस से संक्रमित होने का खतरा है।
- WHO वर्तमान में HIV PrEP के विकल्पों के रूप में ओरल PrEP, डैपिविरिन वैजाइनल रिंग, और लॉन्ग-एक्टिंग इंजेक्टेबल कैबोटग्रेविर (CAB-LA) की सिफारिश करता है।

HIV के बारे में

- ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) एक वायरस है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है।
- कार्य-प्रणाली: HIV शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं (CD4 कोशिकाओं/ CD4 टी लिम्फोसाइट्स) को संक्रमित कर उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है।
- प्रसार: HIV वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों जैसे- रक्त, स्तन का दूध, सीमन और योनि स्राव से फैलता है।
- यह माता से बच्चे में भी फैल सकता है।
- उपचार: HIV को एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) से रोका और नियंत्रित किया जा सकता है।
- बिना इलाज के HIV आगे चलकर AIDS (एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम) में बदल सकता है।
- HIV अनुमान 2023 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2.5 मिलियन से अधिक लोग HIV संक्रमण से पीड़ित हैं।

भारत की पहलें:

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-V (2021-26): इसका लक्ष्य नए संक्रमणों में 80% की कमी लाना है।
- 95-95-95 लक्ष्य: इसका अर्थ है कि 95% HIV पॉजिटिव लोग अपनी स्थिति को जानें, 95% निदान किए गए लोगों को एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) पर होना चाहिए और 95% मरीजों में वायरस का स्तर इतना कम हो जाए कि वह दूसरों में न फैला सके।
- HIV और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 2017: यह अधिनियम HIV-पॉजिटिव लोगों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है।
- भारत ने 2030 तक HIV/ एड्स को लोक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- भारत के शैक्षणिक संस्थानों में रेड रिबन क्लब जैसी युवा-केंद्रित पहलें भी चलाई जा रही हैं।

## हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को इसरो से 'लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)' बनाने का अनुबंध मिला

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अलावा अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अनुबंध प्राप्त करने की बोली लगाई थी। हालांकि, अंत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ISRO से ट्रांसफर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (ToT) का सौदा मिला।

- इस सौदे के तहत HAL लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) बनाएगा और इसका संचालन करेगा।
- प्रायोगिकी हस्तांतरण चरण के दौरान, HAL को इसरो द्वारा किए गए तीन विकासात्मक प्रक्षेपणों की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कम-से-कम दो SSLVs संपूर्ण रूप से तैयार करने होंगे।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) के बारे में

- SSLV तीन-चरणों वाला ठोस प्रणोदक रॉकेट है।
- इसे 500 किलोग्राम से कम वजन वाले सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित समतल कक्षा (Planar orbit) में प्रक्षेपित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह कम लागत वाला प्रक्षेपण यान है। यह कम समय में ही दूसरे प्रक्षेपण के लिए तैयार हो जाता है।
- यह कई प्रकार के सैटेलाइट्स; जैसे कि स्मॉल, माइक्रो एवं नैनो सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित कर सकता है।

भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार

- अंतरिक्ष क्षेत्र का उद्यमीकरण: निजी संस्थाओं को अब सैटेलाइट निर्माण से लेकर प्रक्षेपण सेवाओं तक, एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी गई है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।
- IN-SPACe का निर्माण: भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) गैर-सरकारी क्षेत्रों की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उन्हें अधिकृत करता है और उनकी निगरानी करता है।
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विनियामक स्पष्टता और लंबे समय के लिए नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
- वेंचर कैपिटल फंड: अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्ट-अप को वित्त-पोषित करने और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का एक विशेष फंड स्वीकृत किया गया है।

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण

- भारत में वर्तमान में अंतरिक्ष प्रायोगिकी में 200 से अधिक स्टार्ट-अप सक्रिय हैं। अब तक ISRO और IN-SPACe/ NSIL द्वारा लगभग 478 प्रायोगिकी हस्तांतरण किए जा चुके हैं।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की पहलें
- विक्रम-S, निजी कंपनी द्वारा निर्मित भारत का पहला रॉकेट है। इसे 'मिशन प्रारंभ' के तहत लॉन्च किया गया था।
- IIT मद्रास-इनक्यूबेटेड स्टार्ट-अप अग्रिकुल कॉसमॉस ने दुनिया के ऐसे पहले रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, जिसमें सिंगल-पीस 3D प्रिंटेड इंजन का प्रयोग किया गया था।

## एक अध्ययन के अनुसार, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) के क्षरण से उत्तरी यूरोप में गंभीर ठंड पड़ सकती है

नीदरलैंड की यूट्रेख्ट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार, मध्यम स्तर के उत्सर्जन के बावजूद यदि AMOC का क्षरण हो जाता है, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि भी उत्तरी यूरोप में इस क्षरण के कारण पड़ने वाली ठंड को पूरी तरह नहीं रोक पाएगी।

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) के बारे में

- महासागरीय धारा: AMOC अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है। यह उष्ण कटिबंध से उत्तरी ध्रुव की ओर गर्म जल धाराओं को प्रसारित करती है। साथ ही ठंडे, खारे व सघन जल को उष्ण कटिबंध तथा दक्षिण ध्रुव की ओर विस्तारित करती है।
- यह प्रणाली तापमान और लवणता की माला में भिन्नता से संचालित होती है-
- गर्म सतही जल ध्रुवों की ओर बढ़ता है और ठंडा हो जाता है।
- जैसे ही समुद्री बर्फ बनती है, यह नमक को पीछे छोड़ने लगती है, जिससे आस-पास का जल सघन हो जाता है।
- सघन जल गहराई की ओर जाता है तथा गहरे समुद्र के स्तर पर दक्षिण की ओर बहता है।
- यह गहरा जल अंततः उद्गलन (Upwelling) के माध्यम से फिर से ऊपर उठता है, गर्म होता है, और चक्र को फिर से शुरू करता है।

महत्व:

- AMOC महासागरीय धाराओं की "वैश्विक कन्वेयर बेल्ट" का हिस्सा है, जो ठंडे और गर्म जल का आदान-प्रदान करती है।
- इस प्रकार, यह लंबे समय तक महासागरों में गर्मी, आर्द्रता और पोषक तत्वों को वितरित करने में मदद करता है।
- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: ग्लोबल वार्मिंग AMOC जैसी प्रमुख महासागरीय धाराओं को कमजोर कर सकती है।
- ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि आर्कटिक की बर्फ पिघलने से उत्तरी अटलांटिक में ठंडा व ताजा जल आता है, जिससे जल की लवणता और घनत्व कम हो जाता है। परिणामस्वरूप, AMOC के गहराई की ओर जाने तथा संचालन के लिए आवश्यक सघन जल दुर्लभ हो जाता है।

यदि AMOC कमजोर हो जाए या उसका क्षरण हो जाए तो क्या होगा?

AMOC का कमजोर होना या क्षरण हो जाना जलवायु के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है, जिसके निम्नलिखित वैश्विक परिणाम होंगे:

- जलवायु व्यवधान: AMOC का थोड़ा सा भी मंद होना
  - यूरोप में ठंड में वृद्धि कर सकता है तथा यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में वर्षा के पैटर्न को बदल सकता है;
  - भारतीय मानसून के समय को प्रभावित कर सकता है;
  - उष्णकटिबंधीय वर्षा बेल्ट को दक्षिण की ओर स्थानांतरित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अफ्रीकी साहेल क्षेत्र में सूखा पड़ सकता है।
  - महासागरीय जीवन के लिए खतरा: कम पोषक तत्व सतही जल तक पहुंचते हैं, जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं को नुकसान पहुंचता है।
- हालांकि, AMOC के पूर्ण क्षरण पर बहस चल रही है, लेकिन इसका वर्तमान में कमजोर होना चिंताजनक है।

## नेशनल टाइम रिलीज स्टडी (NTRS) का पांचवां संस्करण जारी किया गया

टाइम रिलीज स्टडी (NTRS) एक प्रदर्शन माप साधन है, जो कार्गो रिलीज में लगने वाले समय के मातात्मक मूल्यांकन संबंधी जानकारी देता है। यह रिपोर्ट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने तैयार की है। इसका उद्देश्य यह जांच करना है कि देश के पत्तन, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (ACCs), अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICDs) और एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) पर कार्गो कितनी तेजी से क्लीयर (रिलीज) होता है। इससे भारत की लॉजिस्टिक्स प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

रिपोर्ट में 2023 और 2025 के बीच प्रमुख आयात गेटवे पर कार्गो निकासी समय में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई गई है (इन्फोग्राफिक्स देखें)

भारत के लिए लॉजिस्टिक्स क्यों जरूरी है?

एक मजबूत लॉजिस्टिक्स सेक्टर व्यापार को बढ़ाता है, कारोबार की लागत कम करता है और भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ता है। इससे 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाओं को भी सफलता मिलती है।

- रोजगार: लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 2.2 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं।
- प्रतिस्पर्धा: लॉजिस्टिक्स लागत कम होने से भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है।
- वर्तमान स्थिति: 2023 में वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर था, जबकि 2018 में 44वें स्थान पर था।
- 2030 तक का लक्ष्य:

- लॉजिस्टिक्स में दुनिया के टॉप 25 देशों में आना;
- लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 10% से कम करना आदि।

भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सुधार के लिए उठाए गए कदम:

- समर्पित माल भाड़ा गलियारे (DFCs): उत्तरी और पश्चिमी DFCs के बनने से माल ढुलाई में लगने वाला समय 20-30% तक कम हो गया है।
  - अब तक 96% (2,741 किमी) मार्ग चालू हो चुके हैं।
- ई-वे बिल सिस्टम: जीएसटी के तहत शुरू हुआ यह सिस्टम माल की ट्रैकिंग आसान बनाता है और सड़क परिवहन में देरी को कम करता है।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022): इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स की लागत को GDP के 13-14% से घटाकर लगभग 8-9% तक लाना है।
- नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान (NTFAP) 3.0 (2024-27): CBIC द्वारा शुरू की गई यह योजना बंदरगाहों पर कार्गो या माल रिलीज होने में लगने वाले समय को कम करने पर ध्यान देती है।
  - यह WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के अनुरूप है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाया जा सके।

### NTRS क्या है?



#### शुरुआत (Genesis)

वर्ष 2019 से, टाइम रिलीज स्टडी हर साल 15 प्रमुख स्थानों और समुद्री बंदरगाहों पर की जाती है।



#### जिस संस्था द्वारा सिफारिश की गई:

##### वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन (WCO)

यह एक अंतर-सरकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह 186 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है, जो विश्व व्यापार का 98% हिस्सा संभालते हैं।

### 5वें NTRS के मुख्य निष्कर्ष



#### सुधार (समय में कमी):

समुद्री बंदरगाह (SEAPORTS): 6 घंटे की कमी

हवाई माल परिवहन (AIR CARGO - ACCs): 5 घंटे की कमी

चेक पोस्ट्स (ICPs): 18 घंटे की कमी

औसत रिलीज समय घटा है।



#### चुनौतियां (समय में वृद्धि):

इनलैंड कंटेनर डिपो (ICDs): 2023-2025 के बीच 12 घंटे की बढ़ोतरी

## अन्य सुर्खियां



### स्टेबल कॉइन

अमेरिकी सीनेट ने स्टेबल कॉइन्स को बढ़ावा देने के लिए गाइडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स (GENIUS) अधिनियम पारित किया।

स्टेबल कॉइन क्या होते हैं?

- स्टेबल कॉइन एक तरह की क्रिप्टो परिसंपत्ति (Crypto Asset) होती है, जिसकी कीमत किसी दूसरी संपत्ति से जुड़ी होती है, जैसे अमेरिकी डॉलर या सोना आदि।
- बिटकॉइन जैसी अस्थिर क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले, स्टेबल कॉइन की कीमतें ज्यादा स्थिर होती हैं, क्योंकि ये कीमत में उतार-चढ़ाव को कम करने की कोशिश करते हैं।
  - इसी वजह से इन्हें लेन-देन, बचत और पारंपरिक वित्तीय प्रणाली और क्रिप्टो इकोसिस्टम के बीच पुल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।



### इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)

IPPB को वित्त मंत्रालय द्वारा 2024-25 का डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड मिला है। यह सम्मान इसके समावेशी, तकनीक आधारित और नागरिकों को केंद्र में रखकर दी जाने वाली बैंकिंग सेवाओं के लिए दिया गया है।

IPPB (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) के बारे में:

- स्वामित्व: IPPB पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व वाला पेमेंट बैंक है, जो डाक विभाग के अंतर्गत आता है।
- महत्व: यह देश भर के लगभग 1.55 लाख डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करके हर कोने तक अपनी सेवाएं पहुंचाता है।
- पेमेंट बैंक क्या होता है?
- यह ऐसे लोगों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं देता है जिन्हें सामान्य बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पातीं, जैसे- धन जमा करना, धन की निकासी, पैसे भेजना और बिल का भुगतान करना। ये सेवाएं मुख्य रूप से डिजिटल तरीके से दी जाती हैं।
- यह बैंक 2 लाख रुपये तक की जमा स्वीकार कर सकता है और पैसे भेजने व बिल भरने जैसी सुविधाएं देता है। लेकिन यह कर्ज (लोन) नहीं दे सकता और न ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है।



### एंटी-डंपिंग शुल्क

भारत ने चीन से आने वाले एल्युमिनियम फॉयल, प्रेटिलाक्लोर तथा चीन, रूस और ताइवान से आने वाले एसीटोनिट्राइल पर 5 साल के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी क्या है?

- एंटी-डंपिंग ड्यूटी एक प्रकार का सुरक्षात्मक शुल्क (टैक्स) होता है। इसे सरकार द्वारा घरेलू बाजार की सुरक्षा के लिए विदेशी वस्तुओं के आयात पर तब लगाया जाता है जब वे बहुत सस्ते दाम पर बेची जाती हैं।
  - डंपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई विदेशी कंपनी अपने उत्पाद को किसी दूसरे देश में इतनी कम कीमत पर बेचती है, जो उसके अपने देश की कीमत से भी कम होती है।
- GATT (जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड) के तहत देशों को डंपिंग के खिलाफ कदम उठाने की अनुमति दी गई है।



### ओटावा कन्वेंशन

फिनलैंड की संसद ने ओटावा कन्वेंशन (या एंटी-पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन) से हटने की मंजूरी दे दी है।

- इससे पहले एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड भी इस संधि से हटने की घोषणा कर चुके हैं।

ओटावा कन्वेंशन के बारे में:

- शुरुआत: यह संधि 1997 में ओस्लो में हुई एक राजनयिक सम्मेलन में संपन्न की गई थी। इसका मकसद एंटी-पर्सनल लैंड माइंस (भूमिगत बारूदी सुरंगों) पर पूरी तरह रोक लगाना था।
- उद्देश्य: दुनिया भर में एंटी-पर्सनल माइंस से होने वाले नुकसान को रोकना, देशों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, बारूदी सुरंगों को साफ करना, जमा सुरंगों को नष्ट करना और पीड़ितों की मदद करना।
- सदस्यता: अब तक 165 देश इस संधि में शामिल हो चुके हैं। भारत इसका हिस्सा नहीं है।



### ताइवान जलडमरूमध्य

हाल ही में ताइवान ने अपने क्षेत्र के निकट चीनी सैन्य विमान का पता लगाया था। इसके कुछ ही दिन बाद एक ब्रिटिश नौसैनिक जहाज संवेदनशील ताइवान जलडमरूमध्य से होकर गुजरा था।

➤ चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इस स्वशासित लोकतांत्रिक द्वीप को जबरन अपने नियंत्रण में लेने की बात करता है।

ताइवान जलडमरूमध्य (या ब्लैक डिच) के बारे में:

- जलडमरूमध्य एक संकरी जलधारा होती है जो दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है।
- नामकरण: 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इसका नाम फॉर्मोसा (Formosa – “सुंदर”) रखा था।
- यह जलडमरूमध्य दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ता है।
- नदियाँ: चीन की जिउलॉन्ग और मिन नदियाँ इसमें गिरती हैं।
- महत्त्व: यह जलमार्ग दुनिया के 40% से अधिक कंटेनर व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।



### घड़ियाल संरक्षण

उत्तर प्रदेश के कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य में गिरवा नदी में घड़ियाल के सात बच्चों को छोड़ा गया है।

घड़ियालों के बारे में:

- नाम की उत्पत्ति: “घड़ियाल” नाम “घड़ा” (मिट्टी का बर्तन) शब्द से आया है, क्योंकि नर घड़ियालों की थूथन (नाक) पर एक गोल बल्ब जैसा उभार होता है। यह चीज़ उन्हें स्पष्ट रूप से लैंगिक रूप से भिन्न दिखने वाला एकमात्र मगरमच्छ बनाती है।
- आहार: ये मुख्य रूप से मछली खाते हैं।
  - ⊕ इनकी लंबी, पतली थूथन, नुकीले दांत और मजबूत गर्दन इन्हें बेहतरीन मछली शिकारी बनाती है।
- खतरे: बांध, बैराज, और पानी की अत्यधिक निकासी से नदियों की प्राकृतिक बहाव प्रणाली बाधित होती है। इससे नदी झील जैसी बन जाती है और घड़ियाल के लिए अनुपयुक्त हो जाती है।
- आवास: मुख्यतः गंगा नदी की तीन सहायक नदियों में पाए जाते हैं: चंबल नदी (भारत), गिरवा नदी (भारत), राप्ती-नारायणी नदी (नेपाल)

संरक्षण स्थिति:

- ⊕ IUCN (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर): क्रीटीकली इंडेन्जर्ड।
- ⊕ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I में शामिल।
- ⊕ मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, 1975 में शुरू की गई थी।
- ⊕ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में घड़ियाल अभयारण्य स्थापित किए गए हैं।



### वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

जुलाई 2025 से, CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) दिल्ली में पुराने हो चुके बाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगाएगा। यह कदम प्रदूषण कम करने में मदद करेगा।

CAQM के बारे में

- उत्पत्ति: CAQM का गठन CAQM अधिनियम, 2021 के तहत किया गया है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आस-पास के क्षेत्रों (जैसे- हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के लिए कार्य करता है।
- उद्देश्य: वायु प्रदूषण और वायु गुणवत्ता से संबंधित समन्वय, अनुसंधान और समस्या-समाधान में सुधार करना।
- अध्यक्ष: इसका अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसे या तो:
  - ⊕ पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण में कम-से-कम 15 वर्षों का अनुभव हो, या
  - ⊕ प्रशासन में कम-से-कम 25 वर्षों का अनुभव हो।
- मुख्य शक्ति: यदि किसी मामले में मतभेद हो, तो CAQM के आदेशों को राज्य सरकारों, CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), राज्य प्रदूषण बोर्डों और अन्य निकायों के आदेशों से ऊपर मान्यता दी जाती है।



### श्रीशैलम मल्लिकार्जुनस्वामी मंदिर

हाल ही में, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मल्लिकार्जुनस्वामी मंदिर में संरक्षित एक ताम्रपत्र में हेली धूमकेतु का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिला है।

- यह अभिलेख 1456 ईस्वी का है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है।
- इसमें विजयनगर साम्राज्य के शासक मल्लिकार्जुन द्वारा एक वैदिक विद्वान को दी गई अनुदान भूमि का उल्लेख है।

मल्लिकार्जुनस्वामी मंदिर के बारे में

- अवस्थिति: यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, कृष्णा नदी के किनारे नल्लामाला पहाड़ियों पर स्थित है।
- मुख्य देवता: यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। यह मंदिर ज्योतिर्लिंग तथा शक्ति पीठ दोनों के रूप में पूजनीय है।
- संरक्षक: शुरूआत में इसे सातवाहन राजवंश ने संरक्षण दिया, और बाद में राष्ट्रकूट राजवंश और विजयनगर शासकों ने भी इसका संरक्षण किया।

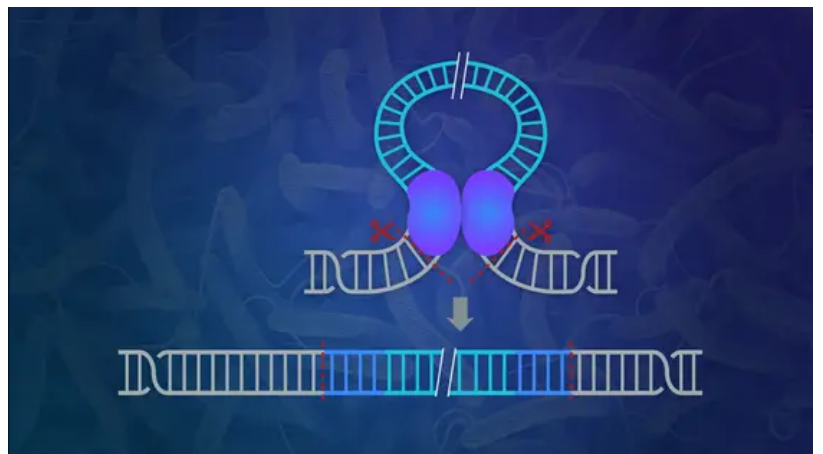


### जंपिंग जीन

एक नए अध्ययन से पता चला है कि LINE-1 नाम का एक “जंपिंग जीन” कोशिका विभाजन की लघु अवधि में कोशिका के DNA से जुड़ जाता है।

जंपिंग जीन क्या होते हैं?

- ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या जंपिंग जीन DNA के ऐसे हिस्से होते हैं जो जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस तरह ये जीन्स के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं।
  - ⊕ ये या तो खुद को काटकर और दूसरी जगह पेस्ट करके ऐसा कर सकते हैं, या अपनी प्रतिकृति बनाकर नई जगह पर जा सकते हैं।
  - ⊕ इस प्रक्रिया में ये जीन में म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं और कोशिका के जीनोम में DNA की माला को बढ़ा या घटा सकते हैं।
- मनुष्यों में 50% से अधिक जीनोम इन्हीं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स से बना होता है।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर